eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

विमुद्रीकरण की सार्थकता

[1]श्री जोखन सिंह
[1]सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय, दर्शन नगर अयोध्या (उ0प्र0)

Received: 20 Jan 2023, Accepted: 28 Jan 2023, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2023

Abstract

भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक और कठोर कदम 8 नवंबर 2016 को उठाते हुए 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रीकरण कर दिया गया। अब कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर 500 और 1000 के नोट वैध मुद्रा नहीं रहे। यह कदम ऐतिहासिक इसलिए है कि इससे पहले प्रथम बार स्वतंत्रता के पूर्व 1946 और दूसरी बार स्वतंत्रता के उपरांत 1978 में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई। परंतु पूरे विश्व के इतिहास में अब तक जब भी यह नीति अपनाई गई, इस नीति का उपयोग अति मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता, व युद्ध की स्थिति से निपटने हेतु ही किया गया और उसमें यह नीति काफी सफल भी रही है।

मुख्य शब्द– भारत की अर्थव्यस्था, भारत में विमुद्रीकरण नीति का अवलोकन एवं विमुद्रीकरण की सार्थकता।

Introduction

पहली बार इस नीति का प्रयोग काला धन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किया गया। दूसरी बात जहां तक इसकी कठोरता का प्रश्न है कठोर इसलिए क्योंकि एक ही झटके में बाजार के 86 प्रतिशत नोटों के प्रचलन को अवैध करार कर दिया गया। जिस के विकल्प के रूप में कोई उपयुक्त व्यवस्था या तैयारी नहीं की गई जिससे आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2008 की वैश्विक मंदी जिसमें की लगभग विश्व के सभी देश प्रभावित हुए भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा इससे निपटने हेतु नकारात्मक वैश्विक नीत, ऋणात्मक ब्याज दर की नीति तथा हेलीकॉप्टर ड्रॉप की नीति को अपनाया गया। यह ऐसे उपाय हैं जिसमें किसी कार्य के लिए आसानी से मुद्रा उपलब्ध हो सके। इस हेतु एक बारगी अधिक मात्रा में मुद्रा की आपूर्ति करना जिससे लोगों के पास क्रय शक्ति हो सके और मांग में वृद्धि हो सके। उस वैश्विक मंदी से अभी भी अर्थव्यवस्थाएं उबर नहीं पाई है क्योंकि अभी भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है ऐसी दशा में भारत जैसे देश में एक बार भी 86 प्रतिशत नोटों के प्रचलन से बाहर निकालना बिना किसी उपयुक्त कारण व इंतजाम के इसे रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्राफ्ट की संज्ञा से अभिभूत किया गया। जिसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्र की गतिविधियों में शिथिलता होना निश्चित है क्योंकि इससे मांग व पूर्ति पक्ष दोनों प्रभावित हुए हैं जहां तक विमुद्रीकरण के उद्देश्य का प्रश्न है यह निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया ।

नंबर 1. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु।
नंबर 2. काला धन पर नियंत्रण हेतु।
नंबर 3. आतंकवाद पर नियंत्रण हेतु ।
नंबर 4. रियल एस्टेट की कीमतों पर नियंत्रण हेतु।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है यह भारत के सामाजिक जीवन में रच बस गया है कोई भी काम बिना कुछ लिए दिए होना असंभव सा हो गया है। फिर भी यदि हम विभिन्न देशों का इतिहास देखें तो यह स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किसी भी देश में आम बात है। लेकिन इसे दूर करने हेतु स्वच्छता, तकनीक, हमारी नियत आदि माध्यमों से ही संभव हो सकता है, उदाहरण के तौर पर हम साफ सुथरी जगह यथा मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए अच्छा व्यवहार करते हैं अपेक्षाकृत यात्री ट्रेनों के। तकनीकि भ्रष्टाचार को दूर करने में बहुत ही कारगर उपाय हो सकती है। वर्तमान समय में सरकारी योजनाओं में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने में मोबाइल, आधार आदि के द्वारा इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है जैसा कि वर्तमान समाज में हम विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होते हुए देख सकते हैं। इसमें कहां तक विमुद्रीकरण की प्रक्रिया सहायक होगी इस संबंध में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी।

काला धन जिसे समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है मूलतः काला धन से तात्पर्य उस धन से हैं जो कानूनी या गैरकानूनी ढंग से कमाया गया हो परंतु उस पर कर नही अदा किया गया है। भारत में काले धन का स्वरूप बहुत बड़े आकार का है काफी मात्रा में काला धन विदेशों में जमा है व देश के अंदर भी काफी मात्रा में विद्यमान है विभिन्न अध्ययनों से ऐसा पता चलता है कि काला धन का अधिकांश भाग रियल स्टेट, मकान, बेनामी संपत्ति व बाजारों में लगा हुआ है। विभिन्न रिसर्च अध्ययनो से स्पष्ट हुआ है कि काली कमाई का अधिकांश भाग विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर देते हैं केवल 6 प्रतिशत हिस्सा ही नगद रूप में अपने पास रखते हैं जब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी तो इस 6 प्रतिशत नगदी को वैध मुद्रा करने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई क्योंकि विभिन्न खातों की सहायता लेकर तथा जनधन या सामान खाते से वह मुद्रा भी वैध मुद्रा हो गई ।

सरकार द्वारा एकबारगी लगभग 16 लाख करोड़ मुद्रा बाजार से निकाला गया था जिसमें अनुमान व्यक्त किया गया था कि लगभग 11 से 12 लाख करोड़ मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था में जमा होंगे और शेष लगभग 500000 करोड मुद्रा बैंक मे जमा नहीं होगी। और जब यह मुद्रा बैंक में जमा नहीं होगी तो सरकार के पास नई मुद्रा जारी करने का एक मजबूत आधार हो जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया।

तीसरे जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है आतंकवादी लोगों के पास काफी मात्रा में जाली नोट व काला धन है जिससे कि वे लगातार सरहद पर व देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल है उनके पास जमा जाली नोट व काला धन अपने आप समाप्त हो जाएगा यह महत्वपूर्ण व विशेष उपाय के रूप में कारगर हो सकता है लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आतंकवादी जो नई नोट जारी की गई उसको प्राप्त करने में असफल होंगे कुछ दिनों तक हो ऐसा सही साबित हो सकता है कि आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित हो परंतु ऐसा देखने को नहीं मिला जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं हाल के दिनों में बढी है उससे यह कह पाना काफी मुश्किल है कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने हेतु विमुद्रीकरण की नीति बहुत कारगर साबित हुई।

जहां तक रियल एस्टेट की कीमतों के नियंत्रण हेतु विमुद्रीकरण की आवश्यता की सार्थकता का सवाल है पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 2008/09 की वैश्विक मंदी आने का मुख्य कारण

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

रियल स्टेट ही था। जिसमें की आवश्यकता से काफी अधिक मकान का निर्माण अधिक ब्याज दर पर बैंकों से ऋण लेकर किया गया और उस लोन का बीमा भी करवाया गया जब मकान बिके नहीं तो बैंक का EMI लोन बिल्डरों को वहन करने में परेशानी हुई जिससे बिल्डर बीमा कंपनियां के पास गए परंतु सभी बिल्डरों की स्थिति एक जैसी थी इसलिए बीमा कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। परिणाम के तौर पर पहले बीमा कंपनियां फिर बैंक और बिल्डर क्रम से दिवालिया हुए। यह संक्रमण कुछ ही समय में सभी क्षेत्रों में फैला जिससे कि वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

पिछले वर्षों में भारत में भी रियल स्टेट की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी, बूम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे कि आम नागरिक हेतु घर का सपना काफी कठिन हो गया था यह गुब्बारा टूटने के कगार पर था उससे पहले ही कीमतें कम होना प्रारंभ हो गई थी। आर्थिक समीक्षा 2016– 2017 के आंकड़ों से 2014 के चौथे चरण से ही कीमती औसत रूप से गिर रही थी। विमुद्रीकरण की नीति ने इसमें आग में घी का काम किया क्योंकि लोगों के पास विमुद्रीकरण के फलस्वरूप सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की समस्या उत्पन्न होने लगी ऐसी स्थिति में जमीन व मकान खरीदना संभव नहीं था। धन निकासी पर तमाम तरह की पाबंदी लगाई गई इससे भी मांग प्रभावित हुई ।

डिजिटलाइजेशन एक प्रमुख उपकरण है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु जहां तक डिजिटलाइजेशन का प्रश्न है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में यह एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है जब विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई तो पूर्व में इसके बारे में सोचा ही नहीं गया था न ही इस हेतु तैयारी की गई थी लेकिन जब नगदी संकट अपना भयानक रूप ले लेने लगा बैंकों में लंबी–लंबी कतारें लगने लगी ऐसी स्थिति से निपटने के विकल्प के रूप में इसे अपनाया गया।

पेटीएम, स्वाइप, फोन पे आज मशीनों के प्रचलन में बहुत तीव्रता आई लेकिन बिना किसी तैयारी के इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना बहुत मुश्किल काम है इस हेतु व्यापक स्तर पर तैयारी की आवश्यकता है लोगों को जागरूक करना विभिन्न उपकरण की सुविधा उपलब्ध कराना, नेटवर्क उपलब्ध कराना व बड़े लेन–देन हेतु डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य करना यह उपाय काफी कारगर हो सकता है। इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है ।

जहां तक विमुद्रीकरण का सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव का प्रश्न है इस हेतु विमुद्रीकरण जनित अल्पकालीन आघात को समझा जाए। कुल मांग में आघात है क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति घटती है जिससे कि लोगों के पास क्रय विक्रय के उद्देश्य एवं लेनदेन के उद्देश्य मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है जिससे कि प्रमुखत दो प्रभाव दिखते हैं।

नंबर एक –प्रत्यक्ष रूप से मांग में कमी होती है।

नंबर दो– पूर्ति पर आघात इसलिए क्योंकि मुद्रा विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने हेतु महत्वपूर्ण साधन है जब बाजार में नकदी की मात्रा काफी कम होगी तो लोगों के पास नकदी की कमी होगी जो विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक कार्य करते हैं ऐसी स्थिति में उनके लिए काम को जारी रख पाना मुश्किल होगा ऐसी स्थिति में काम धंधा प्रभावित होगा जिससे उत्पादकता कम होगी और अंततः इससे पूर्ति पक्ष प्रभावित होगा अर्थात उत्पादन कम होगा।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

तीसरे ऐसी स्थिति में अनिश्चितता का माहौल बना रहता है बार–बार नीतियों में सरकार द्वारा फेर बदल किया गया जिससे कि अस्थिरता का संकट उत्पन्न हो गया जो भी नगदी बैंक से अन्य माध्यमों से लोग प्राप्त कर रहे थे उसे पुनः बैंकिंग व्यवस्था में नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि सामान्य जन में यह धारणा पनप रही थी कि सरकार द्वारा कब नीतियों में परिवर्तन किया कर दिया जाएगा कुछ निश्चित नहीं है। मुद्रा से संबंधित नीति में परिवर्तन होता है तो उससे सामान्यजन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में वह नकदी को वरीयता प्रदान कर रहे थे ।अनुमान व्यक्त किया गया कि इस नीति को अपनाने के उपरांत सकल घरेलू उत्पाद में 0.5 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन सब क्रियाओं अर्थात नई मुद्रा के वितरण की लागत, नए नोट की छपाई की लागत जिसे 15 से 20000 करोड़ रुपए आंका गया है उसका क्या होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण की नीतियां जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनाई गई इसके सफल होने की संभावना कमतर हैं, हां इसके विकल्प के रूप में जो चीजें उभरकर आई जैसे डिजिटलाइजेशन, आधार, भीम एप, फोन पे, गूगल पे, मोबाइल बैंकिंग इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है।

संदर्भ पुस्तकें–

1. –योजना
2. –आर्थिक समीक्षा 2016–17
3. –कुरुक्षेत्र
4. –प्रतियोगिता दर्पण
5. –भारतीय अर्थव्यवस्था दत्त एवं सुंदरम
6. –भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र एवं पुरी
7. –सर्वेक्षण तथा विश्लेषण प्रो यस यन लाल